NYCS
RNI: DELBIL/2008/25219, ₹20

युवा सहकार

www.nycsindia.com
अगस्त 2025, नई दिल्ली

राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 घोषित

युवाओं के लिए खुले अवसरों के द्वार, बनेंगे विकसित भारत के सूत्रधार

युवाओं को सहकारिता से जोड़ने की रणनीति 15
22 पहली बार कच्छ में बनी नमक कोऑपरेटिव

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

KRIBHCO
Cooperative and beyond...

SERVING **FARMERS** **TO GROW** BOUNTIFUL

KRIBHCO world's premier fertilizer producing cooperative has been consistently making sustained efforts towards promoting modern agriculture and cooperatives in the country. It helps farmers maximize their returns through specialised agricultural inputs and other diversified businesses.

KRISHAK BHARATI COOPERATIVE LTD

Registered Office: A-60, Kailash Colony, New Delhi-110048 | **Phone: 011-29243412**
Corporate Office: KRIBCHO BHAWAN, A 8-10, Sector-1, Noida-201301, Distt: Gautam Budh Nagar (UP) | **Phones:** 0120-2534631/32/36
Website: www.kribhco.net | **KRIBCHO Kisan Helpline:** 0120-2535628 | **E-mail:** krishipramarsh@kribhco.net

OUR PRODUCTS

Neem Coated Urea | DAP | MOP | NPK | NPS | MAP | Liquid Bio Fertilizers | Certified Seeds | Hybrid Seeds
City Compost | Zinc Sulphate | Natural Potash | Sivarika | Rhizosuper

युवा सहकार

वर्ष : 02, अंक-02, अगस्त-2025

निदेशक मंडल
एनवाईसीएस

प्रकाश चंद्र साहू
मनीष कुमार
राजेश बाबूलाल पांडे
प्रकृति क्षितिज पंड्या
बालू गोपालकृष्णन
ज्योतिर्मय सिंह महतो
गौरव पांडेय
हिरेन मधुसूदन शाह
राघव गर्ग
आशुतोष सतीश गुप्ता

कार्यालय

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस)
209, द्वितीय तल, ए2बी, वर्द्धमान जनक मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058
मोबाइल नंबर : 9205595944
लैंडलाइन नंबर : 011-45096652/40153681
E-mail: nycs.ltd@gmail.com
Web: www.nycsindia.com

Registration No DELBIL/2008/25219

संकल्पना, कंटेंट व डिजाइन : फार्च्यूना कम्यूनिकेशंस प्रा. लि., नई दिल्ली

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एवं मित्तल प्रिंट एन पैक, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-92 द्वारा मुद्रित।

अभिषेक कुमार: पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के उत्तरदायी।

NYCSIndia

युवाओं को सहकारिता से जोड़ेगी नई नीति 04
केजे पटेल इफको के नए एमडी 05

06 युवाओं के लिए खुले अवसरों के द्वार, बनेंगे विकसित भारत के सूत्रधार

15 युवाओं को सहकारिता से जोड़ने की रणनीति

एनवाईसीएस की गतिविधियां और उपलब्धियां 16
पहली बार कच्छ में बनी नमक कोऑपरेटिव 22
सहकारी समितियों को मिलेगी आर्थिक मजबूती 25
टेस्ट में बेस्ट गिल की युवा टीम 27
सफलता में एनवाईसीएस बनी मददगार 30

युवाओं को सहकारिता से जोड़ेगी नई नीति

सहकारी शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। नए और उभरते क्षेत्रों में सामाजिक उद्यम इनक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे, जो ग्रामीण और सामुदायिक स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देंगे। नई नीति में राष्ट्रीय डिजिटल सहकारी रोजगार एक्सचेंज की स्थापना का सुझाव दिया गया है, जो योग्य उम्मीदवारों और सहकारी संस्थाओं के बीच सीधा और पारदर्शी संपर्क सुनिश्चित करेगा।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा 24 जुलाई को बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किया गया जिसने 2002 में बनी नीति की जगह ली है। सहकारिता के माध्यम से समृद्धि लाकर 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना नई नीति का विजन है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर देश की अर्थव्यवस्था में सहकारी क्षेत्र का योगदान बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सहकारिता से जोड़ना और उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना इसका मकसद है। इसके केंद्र बिंदु में गांव, कृषि, युवा, ग्रामीण महिलाएं, दलित और आदिवासी हैं।

नई नीति में यह लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2034 तक अर्थव्यवस्था में सहकारी क्षेत्र का योगदान तीन गुना बढ़े और आगामी 10 वर्षों में 50 करोड़ लोग सहकारी ढांचे से जुड़ें। इसके लिए सहकारी समितियों की संख्या में 30 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। हर तहसील में 5-5 मॉडल सहकारी गांव विकसित करने के साथ हर गांव में कम से कम एक सहकारी समिति की स्थापना करने का लक्ष्य इसमें तय किया गया है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के युवाओं को सहकारी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के लिए तकनीकी कौशल से दक्ष बनाने का प्रावधान इसमें किया गया है। सहकारिता अर्थव्यवस्था की बुनियाद का प्रमुख हिस्सा बन सके, इसके लिए बीते दो दशकों में हुए परिवर्तन के अनुरूप इस नीति में प्रावधान किए गए हैं। यह अगले दो दशक तक भारतीय सहकारिता आंदोलन को और मजबूत करने तथा व्यापक विस्तार देने का काम करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर की 48 सदस्यीय समिति ने नई नीति तैयार की है। इस समिति में राष्ट्रीय व राज्य सहकारी संघों सहित सभी स्तरों और क्षेत्रों की सहकारी समितियों के सदस्य, केंद्र और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों के प्रतिनिधि और शिक्षाविद शामिल किए गए थे।

राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के माध्यम से गांव-गांव तक सहकारिता आंदोलन को पहुंचाने के लिए 6 स्तंभ, 16 उद्देश्य और 82 कार्य नीतियां निर्धारित की गई हैं। 6 स्तंभों में नींव का सशक्तीकरण, जीवंतता को प्रोत्साहन, सहकारी समितियों को भविष्य के लिए तैयार करना, समावेशिता को बढ़ावा और पहुंच का विस्तार, नए क्षेत्रों में विस्तार और सहकारी विकास के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना शामिल है। सहकारी शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। नई नीति में राष्ट्रीय डिजिटल सहकारी रोजगार एक्सचेंज की स्थापना का सुझाव दिया गया है, जो योग्य उम्मीदवारों और सहकारी संस्थाओं के बीच सीधा और पारदर्शी संपर्क सुनिश्चित करेगा। साथ ही, एक राष्ट्रीय शिक्षक और प्रशिक्षक डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा, जिससे नियुक्ति की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित हो सकेगी। इसके माध्यम से राज्यों के सहकारिता कानूनों में आवश्यक सुधार किए जाएंगे, ताकि सहकारी समितियों को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और व्यावहारिक प्रणाली के अंतर्गत कार्य करने का अवसर मिले।

दुनिया के लिए सहकारिता एक मॉडल है, लेकिन भारत के लिए यह संस्कृति का आधार और एक जीवनशैली है। सहकारिता वह शक्ति है जो व्यक्ति की शक्तियों को सामूहिक रूप से लाकर समाज की शक्ति के रूप में परिवर्तित करती है। देश के 140 करोड़ लोगों को साथ रखकर अर्थतंत्र का विकास करने की क्षमता केवल और केवल सहकारिता क्षेत्र में है। नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस) भी पिछले 25 वर्ष से युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें सहकारिता से जोड़ने में अग्रसर है। नई नीति के माध्यम से एनवाईसीएस इसे और आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी।■

प्रकाश चंद्र साहू
अध्यक्ष, नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

केजे पटेल इफको के नए एमडी

युवा सहकार टीम

देश और दुनिया की नंबर एक फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) के प्रबंधन में 32 साल बाद ऐतिहासिक बदलाव हुआ। वर्ष 1993 में किसानों की इस सबसे बड़ी सहकारी संस्था के प्रबंध निदेशक का पद संभालने वाले डॉ. उदय शंकर अवस्थी 31 जुलाई को 80 वर्ष की उम्र में अपने पद से रिटायर हो गए। उनकी जगह इफको के डायरेक्टर (टेक्नीकल) कृतिकुमार जे पटेल को नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। पटेल इफको के 9वें प्रबंध निदेशक हैं और उनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की गई है। राजकोट स्थित सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाले पटेल को नाइट्रोजनयुक्त एवं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर प्लांटों के रखरखाव का 32 वर्षों का अनुभव है।

इफको के चेयरमैन दिलीप संघाणी ने उनकी नियुक्ति की घोषणा करते हुए कहा, 'केजे पटेल तकनीकी उत्कृष्टता और किसान-केंद्रित सोच का प्रतीक हैं। उनका गहन उद्योग ज्ञान और सिद्ध रणनीतिक सोच इफको के लक्ष्यों से पूरी तरह मेल खाता है। वह डॉ. अवस्थी की विरासत को आगे बढ़ाने में पूरी तरह सक्षम हैं। बोर्ड को पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में इफको उत्कृष्टता और भारतीय किसानों की सेवा की अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाएगा। वह इफको को नवाचार और मूल्य सृजन के एक नए युग में ले जाएंगे।' संघाणी ने डॉ. अवस्थी को इफको एवं देशभर के किसानों के प्रति उनके अमूल्य योगदान एवं समर्पण के लिए धन्यवाद भी दिया। डॉ. अवस्थी ने लंबे समय तक न सिर्फ संगठन का नेतृत्व किया, बल्कि इसे वैश्विक पहचान दिलाते हुए दुनिया की नंबर एक फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव बना दिया। कृषि और सहकारिता क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनमें अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन द्वारा दिया गया रॉशडेल पायोनियर्स अवार्ड और सहकार भारती द्वारा दिया गया फर्टिलाइजर मैन ऑफ इंडिया सहित कई सम्मान शामिल हैं। वह इंटरनेशनल फर्टिलाइजर एसोसिएशन और फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया में भी नेतृत्वकारी भूमिका में रहे।

नौवें प्रबंध निदेशक की पांच वर्ष के लिए हुई नियुक्ति, फर्टिलाइजर प्लांटों के मेंटेनेंस का है 32 वर्ष का अनुभव

केजे पटेल ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'हमारे देश में फर्टिलाइजर का जो उत्पादन हो रहा है उसमें इफको 95 लाख टन का योगदान दे रहा है। मेरा फोकस है कि पारंपरिक उर्वरकों, खासकर यूरिया, डीएपी और फास्फेटिक उर्वरकों की कमी न होने पाए। जियो पॉलिटिकल परिस्थितियों की वजह से कच्चे माल के आयात में बहुत बाधाएं आ रही हैं। मेरी पहली प्राथमिकता उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने की है। दूसरी प्राथमिकता नैनो फर्टिलाइजर को प्रत्येक किसान तक पहुंचा कर उसके उपयोग और उसके फायदे के बारे में जागरूकता लाना है ताकि उसका इस्तेमाल बढ़े।'

केजे पटेल ने इफको के कलोल प्लांट में 23 वर्षों तक कार्य किया और 2012 में ओडिशा स्थित पारादीप यूनिट के हेड बने। यह भारत का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर प्लांट है। उनके नेतृत्व में इस प्लांट ने ऑपरेशनल एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी और मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। 2016 में उन्हें जीएम (मेंटेनेंस) बनाया गया और नई दिल्ली स्थित इफको मुख्यालय बुला लिया गया। बाद में उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर (टेक्नीकल) की जिम्मेदारी सौंपी गई।

पटेल के एमडी का पदभार ग्रहण करने के बाद इफको के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अब छह गैर-निर्वाचित डायरेक्टर्स रह गए हैं जिनमें से पांच सेवा विस्तार पर चल रहे हैं। दिलीप संघाणी ने कहा, 'प्रोन्नत और प्रोत्साहन देने के लिए इफको के बोर्ड में नए लोगों को मौका दिया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो सेवा विस्तार वाले डायरेक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा, ताकि उनके अनुभव का लाभ संगठन को मिलता रहे।' ■

राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 घोषित

युवाओं के लिए खुले अवसरों के द्वार, बनेंगे विकसित भारत के सूत्रधार

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के युवाओं को सहकारी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के लिए तकनीकी कौशल से दक्ष बनाने का प्रावधान

युवा सहकार टीम

सहकारिता को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में लाकर उसे विकसित भारत का सूत्रधार बनाने के लिए सरकार अब गांव, कृषि, ग्रामीण महिलाएं, दलित और आदिवासियों की मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है। जुलाई के आखिरी सप्ताह में घोषित नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति के तहत इस मकसद को पाने के उपाय किये गये हैं। इनसे न केवल इन वर्गों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने में मदद मिलेगी बल्कि उनमें सहकारिता की भावना भी मजबूत होगी। केंद्रीय गृह एवं

हर तहसील में 5-5 मॉडल सहकारी गांव विकसित करने के साथ हर गांव में कम से कम एक सहकारी समिति की स्थापना करने का लक्ष्य

वर्ष 2034 तक अर्थव्यवस्था में सहकारी क्षेत्र का योगदान तीन गुना बढ़ाना और आगामी 10 वर्षों में 50 करोड़ लोगों को सहकारी ढांचे से जोड़ना

सहकारी समितियों की संख्या में 30 प्रतिशत की वृद्धि करना, राष्ट्रीय सहकारिता नीति के केंद्र बिंदु में गांव, कृषि, ग्रामीण महिलाएं, दलित और आदिवासी

सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का अनावरण करते हुए कहा कि यह अगले दो दशकों के लिए भारत के सहकारी आंदोलन में मील का पत्थर साबित होगी।

सरकार मानती है कि सहकारिता नीति 2025 सहकारी आंदोलन को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भारत में बीते दो दशकों में हुए बदलावों के अनुरूप प्रावधान किये गये हैं ताकि सहकारिता को अर्थव्यवस्था की बुनियाद का प्रमुख हिस्सा बनाया जा सके। देश में सहकारिता का इस्तेमाल केवल व्यक्तिगत अथवा बेहद छोटे समूहों के उत्थान के लिए किया जाता रहा था। लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे एक व्यापक नजरिया प्रदान किया है। यही वजह है कि केंद्र में इसके लिए अलग से एक मंत्रालय गठित किया गया और अर्थव्यवस्था की मौजूदा जरूरतों के अनुरूप नई नीति की आवश्यकता महसूस की गई। अभी तक देश में वर्ष 2002 में बनी सहकारिता नीति के मुताबिक काम हो रहा था।

नई नीति सहकारिता को ग्रामीण भारत की आर्थिक रीढ़ के रूप में सशक्त बनाने के साथ-साथ युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों को एक समावेशी और आत्मनिर्भर विकास मॉडल से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करेगी। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और आधुनिक बनाने के साथ-साथ जमीनी स्तर पर एक रोडमैप बनाकर सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करना है। जबकि पिछली राष्ट्रीय सहकारिता नीति में सहकारी संस्थाओं की आर्थिक गतिविधियों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक आधारभूत रूपरेखा दी गई थी। पिछले 20 वर्षों में वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति के कारण समाज, देश और विश्व में कई बड़े परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए नई नीति बनाना आवश्यक हो गया था, ताकि सहकारी संस्थाओं को वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में अधिक सक्रिय और उपयोगी बनाया जा सके और ''विकसित भारत 2047'' के लक्ष्य को हासिल करने में सहकारिता क्षेत्र की भूमिका मजबूत हो सके।

राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के अनावरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, 'नई सहकारिता नीति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन

"दुनिया के लिए सहकारिता एक मॉडल है, लेकिन भारत के लिए यह संस्कृति का आधार और एक जीवनशैली है।"

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

को पूरा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मोदी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2027 तक हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरेंगे। देश के 140 करोड़ लोगों को साथ रखकर अर्थतंत्र का विकास करने की क्षमता केवल और केवल सहकारिता क्षेत्र में है। सहकारिता के माध्यम से समृद्धि लाकर 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना नई नीति का विजन है। जबकि पेशेवर, पारदर्शी, तकनीक से युक्त, जिम्मेदार और आर्थिक रूप से स्वतंत्र व छोटी-छोटी सफल सहकारी इकाइयों को बढ़ावा देना और प्रत्येक गांव में कम से कम एक सहकारी समिति स्थापित करना इसका मिशन है। नई नीति में वर्ष 2034 तक सहकारी क्षेत्र का देश की जीडीपी में योगदान तीन गुना बढ़ाने, 50 करोड़ नागरिकों को सहकारी क्षेत्र का सक्रिय सदस्य बनाने और सहकारी समितियों की संख्या में 30 प्रतिशत की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।'

> **सहकारिता वह शक्ति है जो व्यक्ति की शक्तियों को सामूहिक रूप से लाकर समाज की शक्ति के रूप में परिवर्तित करती है।**
>
> **अमित शाह**
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

वर्तमान में देश में 8.30 लाख सहकारी समितियां हैं। प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक प्राथमिक सहकारी समिति स्थापित करने का लक्ष्य नई नीति में रखा गया है। ये प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स), प्राथमिक डेयरी, प्राथमिक मत्स्य पालन समिति, प्राथमिक बहुउद्देश्यीय पैक्स या अन्य प्राथमिक इकाई हो सकती है। इनके माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ाए जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि पारदर्शिता, वित्तीय स्थिरता और संस्थागत विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रत्येक इकाई को सशक्त करना होगा। इसके लिए एक क्लस्टर और निगरानी तंत्र भी विकसित किया जाएगा। नई नीति में सहकारिता क्षेत्र के लिए तय किए गए लक्ष्य को हासिल करने के छह स्तंभ निर्धारित किए गए हैं जिनमें नींव का सशक्तीकरण, जीवंतता को प्रोत्साहन, सहकारी समितियों को भविष्य के लिए तैयार करना, समावेशिता को बढ़ावा और पहुंच का विस्तार, नए क्षेत्रों में विस्तार और

सहकारी विकास के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना शामिल है। भारतीय सहकारी आंदोलन को जमीनी स्तर पर मजबूत और सघन बनाने के लिए एक सक्षम विधिक, आर्थिक और संस्थागत संरचना का सृजन करना तथा सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी उद्यमों को पेशेवर रूप से प्रबंधित, पारदर्शी, तकनीक संपन्न, जीवंत और जिम्मेदार आर्थिक इकाइयों में रूपांतरित होने में सहायता करना इस नीति का मिशन है।

नींव का सशक्तीकरण

सहकारी आंदोलन की नींव को मौजूदा चुनौतियों का समाधान करके, एक सक्षम वातावरण बनाकर और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाकर और सशक्त किया जाएगा। इसके लिए समयबद्ध सुधारों के माध्यम से अनुकूल विधिक और विनियामक माहौल निर्मित करके सहकारी समितियों को स्वायत्तता प्रदान करना, पारदर्शिता, सुगम व्यवसाय और सुशासन को बढ़ावा देने के साथ-साथ उन्हें समान अवसर प्रदान किया जाएगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को अपने संबंधित सहकारी सोसाइटी अधिनियमों और नियमों में जरूरत के अनुसार संशोधन करना होगा ताकि सहकारी समितियों में स्वायत्तता, सुगम व्यवसाय में वृद्धि और सुशासन को बढ़ावा मिल सके। सहकारी समितियों में स्वायत्त कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक रूप से कार्य, सेवाओं की समयबद्ध और पारदर्शी डिलीवरी की एक व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। साथ ही समिति के निदेशक मंडल और पदाधिकारियों का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव तथा पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। जमीनी स्तर पर कार्यान्वित की जा रही सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए पैक्स को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में निर्दिष्ट कर उनकी भूमिका को सशक्त करने और अच्छा प्रदर्शन करने वाले पैक्स को प्रोत्साहित करने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। कॉरपोरेट संस्थानों की तरह ही सहकारी समितियों को सुगम और किफायती वित्त तथा समान व्यावसायिक अवसर प्रदान करने का प्रावधान भी इसमें किया गया है।

वित्तीय समावेशिता की प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए पैक्स, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रत्येक पंचायत में पैक्स, प्रत्येक जिले में एक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और प्रत्येक शहरी क्षेत्र में एक शहरी सहकारी बैंक का होना सुनिश्चित किया जाएगा। जहां ये नहीं हैं वहां इनकी स्थापना की जाएगी। सहकारी बैंकों को व्यवहार्यता के आधार पर नई शाखाएं खोलने और वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं में विविधीकरण द्वारा अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए सहकारिता में सहकार, सहकारी संरचना का सशक्तीकरण और उनकी भौगोलिक पहुंच का विस्तार करना भी शामिल है।

सुरेश प्रभु के नेतृत्व में ड्राफ्ट कमेटी ने निभाई अहम भूमिका

सहकारिता मंत्रालय के 'सहकार से समृद्धि' के लक्ष्य को पूरा करने के लिए नई राष्ट्रीय सहकारी नीति (एनसीपी) के निर्माण की परिकल्पना की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर की 48 सदस्यीय समिति ने नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार की है। इस समिति में राष्ट्रीय व राज्य सहकारी संघों सहित सभी स्तरों और क्षेत्रों की सहकारी समितियों के सदस्य, केंद्र और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों के प्रतिनिधि और शिक्षाविद शामिल किए गए थे। एक सहभागी और समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए इस समिति ने अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुरुग्राम और पटना में 17 बैठकें कीं और चार क्षेत्रीय कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं। इनमें हितधारकों से प्राप्त 648 बहुमूल्य सुझावों को मसौदा नीति में उचित रूप से शामिल किया गया और सावधानीपूर्वक मूल्यांकन कर उन्हें नई सहकारिता नीति में शामिल किया गया है। नई नीति में सहकारिता क्षेत्र की वास्तविक क्षमता को सामने लाने और समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के व्यावहारिक प्रावधान किए गए हैं।

जमीनी स्तर पर कार्यान्वित की जा रही सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए पैक्स को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में निर्दिष्ट कर उनकी भूमिका को सशक्त करने और अच्छा प्रदर्शन करने वाले पैक्स को प्रोत्साहित करने का प्रावधान भी इसमें किया गया है।

सहकारी समितियों की जीवंतता बनाए रखने के लिए भारत ब्रांड के तहत सभी जैविक, कृषि और डेयरी उत्पादों की ब्रांडिंग करने और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापित ब्रांड का लाभ लेने के लिए समितियों को प्रोत्साहित करने की भी रणनीति नई नीति में बनाई गई है। सहकारी समितियों को अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के विभिन्न मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करने का प्रावधान है जिससे उनके ब्रांड का प्रदर्शन होगा और उनकी बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी। अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बढ़ने से समितियों का कारोबार बढ़ेगा जिससे सदस्यों की आय में वृद्धि होगी।

जीवंतता को प्रोत्साहन

नई सहकारिता नीति में सदस्यों की अधिक आय के लिए सहयोग तंत्र के रूप में सहकारी समितियों की जीवंतता और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता की परिकल्पना की गई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहकारी इकोसिस्टम और उसके बहुआयामी विस्तार के प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भर व्यवसाय सहयोग तंत्र के प्रोत्साहन द्वारा सहकारी व्यवसाय की वृद्धि और विकास के लिए जीवंत इकोसिस्टम के सृजन को बढ़ावा देने की रणनीति बनाई गई है। यह तंत्र आसान फाइनेंस, व्यवसाय अनुसंधान और परामर्शी सेवाओं जैसे मार्केटिंग, ब्रांडिंग आदि के साथ-साथ इस पूरे क्षेत्र का विकास और क्षमता निर्माण संस्थानों को सहयोग प्रदान करेगा। बहुउद्देशीय पैक्स को ग्रामीण विकास के इंजन के रूप में केंद्रित कर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश को प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श सहकारी गांव के विकास के लिए प्रोत्साहित करना होगा। जिले के अन्य गांवों को इस आदर्श गांव की बराबरी करने और उसके बाद राज्य में श्रेष्ठ बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत सहकारी समितियों को भौगोलिक संकेतक, बौद्धिक संपदा अधिकार और ट्रेडमार्क के माध्यम से मार्केटिंग के अवसरों को ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

सहकारी समितियों की जीवंतता बनाए रखने के लिए भारत ब्रांड के तहत सभी जैविक, कृषि और डेयरी उत्पादों की ब्रांडिंग करने और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापित ब्रांड का लाभ लेने के लिए समितियों को प्रोत्साहित करने की भी रणनीति नई नीति में बनाई गई है। सहकारी समितियों को अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के विभिन्न मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करने का प्रावधान है जिससे उनके ब्रांड का

प्रदर्शन होगा और उनकी बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी। अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बढ़ने से समितियों का कारोबार बढ़ेगा जिससे सदस्यों की आय में वृद्धि होगी। सहकारी समितियों के दायरे में 50 करोड़ लोगों को शामिल करने के लिए आर्थिक संरचना का सृजन करने तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी क्षेत्र के योगदान को आगामी 10 वर्षों में तीन गुना करने का मार्ग प्रशस्त करने की सिफारिश के लिए एक कार्यबल का गठन किया जाएगा।

सहकारी समितियों को भविष्य के लिए तैयार करना

सहकारी समितियों में प्रभावशाली और पारदर्शी प्रबंधन के लिए नई-नई टेक्नोलॉजी का अपनाया जाना जरूरी है। उन्हें अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने, इन्फ्रास्ट्रक्चर, उत्पादों और सेवाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक पेशेवर प्रबंधित आर्थिक संस्था बनाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए डेटा आधारित निर्णय लेने और बेहतर सेवा डिलिवरी के लिए 'कोऑपरेटिव स्टैक' तैयार करने और उसे विकसित कराने में सहायता करने का प्रावधान राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 में किया गया है। इस पहल का लक्ष्य सहकारी समितियों में उच्च गुणवत्ता वाले डेटा का संग्रह करना और नवाचार तथा नई सेवाओं के सृजन के लिए उसे हितधारकों को आसानी से उपलब्ध कराना है। नई नीति में कहा गया है कि इस स्टैक का विकास मौजूदा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के आधार पर किया जा सकता है, जिसमें अन्य उपयुक्त डेटाबेस भी शामिल किए जा सकते हैं। वर्तमान में विकासाधीन 'कृषि स्टैक' के साथ इसका एकीकरण किया जा सकता है, जो अन्य बातों के अलावा कृषि मंत्रालय के डेटाबेस के साथ सहकारी बैंकों का डेटा एकीकरण करके ब्याज अनुदान की रियल टाइम रिलीज में सुविधा प्रदान करेगा। ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच और उत्पादों का बेहतर दाम पाने के लिए सहकारी समितियों को जेम, ओएनडीसी जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ाने की बात भी इसमें कही गई है।

सहकारी समितियों को भविष्य के लिए तैयार करने की रणनीति के तहत सहकारी सिद्धांतों पर आधारित पेशेवर प्रबंधित आर्थिक इकाई में बदलना जरूरी है। इसके लिए उद्योग की जरूरतों के अनुसार शिक्षा और आवश्यकता आधारित क्षमता निर्माण के लिए समेकित, मानकीकृत और गुणवत्ता के प्रति सजग राष्ट्रीय स्तर की संस्थागत संरचना द्वारा सहकारी समितियों के संगठनात्मक प्रबंधन को पेशेवर बनने के लिए प्रोत्साहन देने की पहल की गई है। इस उद्देश्य को एक शीर्ष

सहकार से समृद्धि की ओर बढ़े कदम

- ✧ विकसित भारत 2047 के विजन में योगदान देगी राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025
- ✧ सहकारिता आधारित आर्थिक संरचना को सुदृढ़ करने, नीतिगत सुधारों की आधारशिला रखने और ग्रामीण जनों तक समृद्धि पहुंचाने का आधार बनेगी नई नीति
- ✧ आगामी दो दशकों के लिए भारतीय सहकारी आंदोलन में मील का पत्थर बनेगी नई नीति
- ✧ नई नीति का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को पुनर्जीवित करना और आधुनिक बनाना है
- ✧ जमीनी स्तर पर रोडमैप बनाकर 'सहकार से समृद्धि' के विजन को करेगी साकार
- ✧ वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में सहकारी समितियों को जीवंत बनाएगी नई नीति
- ✧ इस नीति से टूरिज्म, टैक्सी, इंश्योरेंस और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भी सहकारी समितियां बन पाएंगी
- ✧ डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से श्वेत क्रांति 2.0 के जरिए महिला सशक्तीकरण और रोजगार को बढ़ावा देना
- ✧ तिलहन, दलहन, मक्का और मोटे अनाज की पैदावार बढ़ाकर खाद्य आत्मनिर्भरता को मजबूत करना
- ✧ सहकारी शुगर मिलों को वैकल्पिक स्रोतों से एथनॉल उत्पादन के लिए प्रोत्साहन
- ✧ सहकारी संस्थाओं को 'एक जिला एक उत्पाद' जैसी योजनाओं से जोड़कर निर्यात को बढ़ावा देना
- ✧ शहद, मसाले, चाय, कॉफी, रेशम, फूल व मशरूम जैसे ग्रामीण विशेष उत्पादों के क्लस्टर विकसित करना
- ✧ ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देकर भारत को आत्मनिर्भर व वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाना
- ✧ सहकारी संस्थाओं को समावेशी बनाने, उनका पेशेवर तरीके से प्रबंधन करने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना

सहकारी समितियों में प्रभावशाली और पारदर्शी प्रबंधन के लिए नई-नई टेक्नोलॉजी का अपनाया जाना जरूरी है।

संगठन की स्थापना द्वारा प्राप्त किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर के निकाय के रूप में कार्य करते हुए यह शीर्ष संगठन सहकारी क्षेत्र की मौजूदा शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों/केंद्रों के अखिल भारतीय नेटवर्क का सृजन करेगा और शिक्षकों की नियुक्ति, प्रवेश मानदंड, अध्ययन सूची, पाठ्यक्रम, परीक्षा, इत्यादि को विनियमित करेगा।

देश की पहली सहकारिता यूनिवर्सिटी त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी इस उद्देश्य को पूरा करने में मददगार साबित होगी। यह यूनिवर्सिटी सहकारी क्षेत्र के लिए युवा एवं योग्य श्रमबल की स्थायी और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगी, कौशल संबंधी पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए मौजूदा कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के साथ तालमेल बिठाएगी, सहकारी क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम व अध्ययन सूची तैयार करने के साथ-साथ अनुसंधान और विकास का संचालन करेगी और प्रोत्साहन देगी। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में सहकारिता केंद्रित पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करना, सहकारी शिक्षा, कौशल विकास और सहकारिता के विभिन्न स्तरों एवं विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों में सहकार विशिष्ट गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सामग्री को विभिन्न भारतीय भाषाओं में तैयार करने के लिए केंद्र/राज्य सरकारों के पास उपलब्ध सहकारी शिक्षा फंड (सीईएफ) और इससे संबंधित भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के पास उपलब्ध फंड के उपयोग को भी इसके तहत बढ़ावा दिया जाएगा।

समावेशिता को बढ़ावा देना और पहुंच का विस्तार करना

समाज के सभी वर्गों के व्यापक प्रतिनिधित्व के साथ-साथ युवाओं और महिलाओं को सहकारी तंत्र में शामिल किए जाने को इस नीति में प्राथमिकता दी गई है। इसमें सहकारिता को एक जन आंदोलन के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए सहकारी परिसंघों की भागीदारी और सहभागिता की परिकल्पना की गई है। समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन आदि) की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और सहकारी समितियों में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका देने की बात नई नीति में कही गई है। मत्स्यिकी, डेयरी, हथकरघा, हस्तशिल्प, लघु वनोत्पाद जैसे क्षेत्रों में कमजोर और सीमांत वर्गों की सहकारी समितियों को बढ़ावा देना और उन्हें सशक्त करना भी इसका उद्देश्य है।

जन आंदोलन के रूप में सहकारी

समाज के सभी वर्गों के व्यापक प्रतिनिधित्व के साथ-साथ युवाओं और महिलाओं को सहकारी तंत्र में शामिल किए जाने को इस नीति में प्राथमिकता दी गई है। इसमें सहकारिता को एक जन आंदोलन के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए सहकारी परिसंघों की भागीदारी और सहभागिता की परिकल्पना की गई है। समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन आदि) की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और सहकारी समितियों में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका देने की बात नई नीति में कही गई है।

समितियों की भागीदारी की उद्देश्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कक्षाओं के स्कूली पाठ्यक्रमों में सहकारिता को एक विषय के रूप में शामिल करना, युवा पीढ़ी, विशेषकर महिलाओं और कमजोर वर्गों को सहकारी समितियों के लाभ से अवगत कराने और उनमें जागरुकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय परिसंघों/संघों को अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इसमें शामिल है। इससे सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा जिससे सदस्यता में वृद्धि होगी।

नए और उभरते क्षेत्रों में विस्तार

यह नीति सहकारी समितियों को भविष्य में अपनी उपस्थिति और सदस्यों का आधार बढ़ाने के लिए उन्हें उपयुक्त नए और उभरते क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह सहकारी समितियों को स्वच्छ ऊर्जा, सतत कृषि, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने जैसे सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में मदद करने के लिए पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं अपनाने को प्रोत्साहित करती है। इसके तहत पैक्स को व्यवहार्यता के आधार पर वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर संस्थाओं में परिवर्तित करने के लिए बहुउद्देशीय बना कर उन्हें प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, गोदामों, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), उचित मूल्य की दुकानों, एलपीजी वितरक, पेट्रोल, डीजल रिटेल आउटलेट, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, ग्रामीण नल जलापूर्ति योजना के अधीन प्रचालन और रखरखाव इत्यादि जैसे नए क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रावधान है। कार्यों में विविधता लाने और सदस्यों की आय को बढ़ाने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों के नए और उभरते क्षेत्र जैसे माइक्रो-बीमा, नवीकरणीय ऊर्जा, जल वितरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, अपशिष्ट प्रबंधन, परिवहन, बायोगैस उत्पादन, मोबाइल एप्लिकेशन आधारित एग्रीगेटर सेवा प्रदाता (जैसे टैक्सी चालकों, घरेलू सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों जैसे प्लंबर, बिजली मिस्त्री आदि की सहकारी समिति) इत्यादि में सहकारी समितियों के प्रवेश को प्रोत्साहित और मजबूत करने पर नई नीति में बल दिया गया है।

नई नीति के 16 उद्देश्य:

- ✧समयबद्ध सुधारों के माध्यम से अनुकूल विधिक और विनियामक माहौल निर्मित करके सहकारी समितियों को स्वायत्तता प्रदान करना, पारदर्शिता, सुगम व्यवसाय और सुशासन को बढ़ावा देना एवं उन्हें समान अवसर प्रदान करना।
- ✧कॉरपोरेट संस्थानों की तरह ही सहकारी समितियों को सुगम और किफायती वित्त तथा समान व्यावसायिक अवसर प्रदान करना।
- ✧सहकारिता में सहकार, सहकारी संरचना का सशक्तीकरण और उनकी भौगोलिक पहुंच का विस्तार करना।
- ✧सहकारी व्यवसाय इकोसिस्टम के विकास को प्रोत्साहित करना।
- ✧अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सहित बहुआयामी विस्तार को प्रोत्साहित करना तथा सदस्यों की आय में वृद्धि करना।
- ✧प्रभावशाली और पारदर्शी प्रबंधन के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाना।
- ✧सहकारी समितियों को सहकारी सिद्धांतों पर आधारित पेशेवर प्रबंधित आर्थिक इकाइयों में रूपांतरित होने में सहयोग करना।
- ✧समावेशिता और सदस्य केंद्रीयता को बढ़ावा देना तथा सहकारी व्यवस्था के माध्यम से देश के सभी हिस्सों और जनता तक पहुंच बनाना।
- ✧युवाओं और महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए सहकारी आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में बढ़ावा देना।
- ✧नए और उभरते क्षेत्रों में सहकारी समितियों के विस्तार को प्रोत्साहित करना।
- ✧सस्टेनेबिलिटी के लिए पर्यावरण अनुकूल आचरणों और सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोत्साहित करना।
- ✧ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के युवाओं को सहकारी उद्यमों में करियर अपनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना।
- ✧मानकीकृत, उच्च-कोटि, सहकार केंद्रित पाठ्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहित करना और प्राधिकृत विषयवस्तु का निर्माण करना।
- ✧सहकारी क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास और कौशल बढ़ाने वाले इकोसिस्टम को बढ़ावा देना।
- ✧सहकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को अंशकालिक विषय विशेषज्ञ, उत्कृष्ट शिक्षकों, अनुदेशकों, प्रशिक्षकों और अतिथि संकाय की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ✧सहकारी समितियों द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति और भावी अभ्यर्थियों के लिए नौकरी ढूंढने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सुगम इकोसिस्टम विकसित करना।

सहकारी विकास के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना

राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 में सहकारी समितियों की सफलता की कहानियों और

सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा जिससे सदस्यता में वृद्धि होगी।

इस नीति के कार्यान्वयन की निगरानी, समग्र मार्गदर्शन, अंतर मंत्रालयीय समन्वय, समय-समय पर समीक्षा आदि के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में सहकारी नीति पर राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया जाएगा।

सहकारिता क्षेत्र की बड़ी हस्तियों की जीवनियों के माध्यम से युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करने की रणनीति अपनाई गई है। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सहकारी मूल्यों एवं सिद्धांतों और सहकारी समितियों की कार्यशैली की उचित समझ को विकसित करने के लिए अनुभव आधारित सहकारी ज्ञान प्रदान करना तथा सहकारी इतिहास, कानून, ऑडिट और लेखांकन, वित्त, शासन और प्रचालन जैसे विभिन्न डोमेन एवं सहकार केंद्रित व्यवसाय प्रबंधन में पेशेवर शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना, सहकारी क्षेत्र में अर्थपूर्ण नियोजन के लिए इसमें ग्रामीण युवाओं को तकनीकी कौशल प्रदान करना और उसे उन्नत करना भी शामिल है। युवाओं, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के युवाओं को सहकारी उद्यमों में दीर्घकालिक करियर अपनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना, मानकीकृत, उच्च-कोटि, सहकार-केंद्रित पाठ्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहित करना और प्राधिकृत विषयवस्तु का निर्माण करना, सहकारी क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास और कौशल बढ़ाने वाले इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। सहकारी समितियों द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति और भावी अभ्यर्थियों के लिए नौकरी ढूंढने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सुगम इकोसिस्टम विकसित करने का प्रावधान भी इसमें है।

इस नीति का कार्यान्वयन सहकारी संघवाद की भावना पर आधारित होगा। इसका प्रभावशाली और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय में एक 'कार्यान्वयन प्रकोष्ठ' स्थापित किया जाएगा। इसे संबंधित विषय, दस्तावेजीकरण, समन्वय, निगरानी, रिपोर्टिंग इत्यादि पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस नीति के कार्यान्वयन की निगरानी, समग्र मार्गदर्शन, अंतर मंत्रालयीय समन्वय, समय-समय पर समीक्षा आदि के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में सहकारी नीति पर राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में सदस्य के रूप में भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों को शामिल किया जाएगा।

साथ ही केंद्र-राज्य समन्वय, कार्यान्वयन समस्याओं का समाधान, आवधिक निगरानी और समीक्षा आदि के लिए सहकारिता सचिव की अध्यक्षता में नीति कार्यान्वयन और निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। इसमें भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के सचिवों, सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी विभागों के सचिवों, प्रधान सचिवों, अपर मुख्य सचिवों, नीति आयोग के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय सहकारी परिसंघों, संघों, समितियों, नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी, एनसीसीटी, वैमनीकॉम आदि के अध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।■

युवाओं को सहकारिता से जोड़ने की रणनीति

युवा सहकार टीम

राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 में सहकारी क्षेत्र को पेशेवर, सशक्त और नवाचार की दिशा में आगे ले जाने का खाका प्रस्तुत किया गया है। यह नीति न केवल सहकारी संस्थानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने पर केंद्रित है, बल्कि इसमें युवाओं को सहकारिता क्षेत्र से जोड़ने की भी पेशकश की गई है। इसके लिए इस नीति के केंद्र में दो प्रमुख पहल हैं। सहकारी शिक्षण-प्रशिक्षण और नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर के एक सर्वोच्च संगठन का निर्माण और सहकारी आंदोलन में युवा पीढ़ी को शामिल करने के लिए एक व्यापक रणनीति।

नई नीति के तहत युवाओं को सहकारी उद्यमों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए सहकारिता से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में पेशेवर शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के युवाओं को सहकारी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल से दक्ष बनाया जाएगा। इसमें कहा गया है कि युवाओं को सहकारी प्रणाली से जोड़ने और उनके प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक शीर्ष संस्था की स्थापना की जाएगी, जो राज्य स्तरीय सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय कर भविष्य के लिए नेतृत्व तैयार करेगी, जिससे सहकारी संस्थाओं का संचालन अधिक पेशेवर रूप से किया जा सके। यह शीर्ष संस्था पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षक नियुक्ति और मूल्यांकन जैसी व्यवस्थाओं का मानकीकरण करेगी। साथ ही, समाज विज्ञान में डिग्री व डिप्लोमा प्रदान करने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों को सहकारिता से जुड़े पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

> **सहकारी शिक्षण-प्रशिक्षण और नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष संगठन बनाने की पहल**

कौशल विकास, नवाचार पर फोकस

इस नीति के अंतर्गत सहकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए एक संगठित तंत्र विकसित किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित या वित्तपोषित प्रशिक्षण संस्थानों का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा, ताकि प्रशिक्षण की व्यवस्था और पहुंच बेहतर हो सके। इसके अलावा, सहकारी शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। साथ ही, नए और उभरते क्षेत्रों में सामाजिक उद्यम इनक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे, जो ग्रामीण और सामुदायिक स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देंगे। नई नीति में राष्ट्रीय डिजिटल सहकारी रोजगार एक्सचेंज की स्थापना का सुझाव दिया गया है, जो योग्य उम्मीदवारों और सहकारी संस्थाओं के बीच सीधा और पारदर्शी संपर्क सुनिश्चित करेगा। साथ ही, एक राष्ट्रीय शिक्षक और प्रशिक्षक डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा, जिससे नियुक्ति की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित हो सकेगी।

रिसर्च और फेलोशिप

सहकारी अर्थव्यवस्था, नवाचार और शासन सुधार जैसे क्षेत्रों में डॉक्टोरल और पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप शुरू करने की योजना भी नई नीति में प्रस्तावित की गई है। इसका उद्देश्य सहकारी मॉडल पर आधारित अकादमिक शोध को बढ़ावा देना है।■

आयोजक

नेशनल युवा को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

एनवाईसीएस की गतिविधियां और उपलब्धियां

जननिधि: नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी (एनवाईसीएस) युवाओं में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने और उनके उद्यमों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए जननिधि नाम से एक माइक्रो फाइनेंस डिवीजन चलाती है। वर्तमान में देश भर के 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में जननिधि के 35 केंद्र संचालित हैं। इसके माध्यम से 40,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष लाभार्थियों को ऋण वितरित किए गए हैं।

पीएमकेवीवाई: एनवाईसीएस राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में प्रशिक्षण साझेदार है। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है, ताकि उन्हें बेहतर आजीविका प्राप्त करने में मदद मिले।

कौशल साथी: कौशल साथी पहल के तहत एनवाईसीएस अखिल भारतीय स्तर पर मानकों के साथ साइकोमेट्रिक टेस्ट और कुशल परामर्श के माध्यम से अभ्यर्थियों को परामर्श देती है, ताकि कौशल द्वारा रोजगार योग्यता को बढ़ाया जा सके।

पर्यटन व सहकारी संस्थाएं : चुनौतियां व अवसर राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी

सीएसआर परियोजनाएं: एनवाईसीएस-कोविडा ने बार्टी (बाबासाहेब अंबेडकर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान), महानगर गैस लिमिटेड, महाराष्ट्र प्राकृतिक गैस लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ विभिन्न सीएसआर (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व) परियोजनाएं शुरू की हैं। वित्त वर्ष 2024-25 तक सीएसआर परियोजनाओं के तहत 5,000 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।

उज्ज्वला दीदी: सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ साझेदारी में ओडिशा में एनवाईसीएस की यह एक और सफल पहल थी। इस कार्यक्रम के तहत संगठन ने ओडिशा के सभी 30 जिलों और 450 ब्लॉकों में 6 महीने की अवधि में 10 हजार जमीनी ऊर्जा उद्यमियों को प्रशिक्षित किया।

पूर्व-शिक्षण मान्यता (आरपीएल) परियोजना: यह अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से सीखने को मान्यता प्रदान करने का एक मंच है, ताकि औपचारिक शिक्षा के समान ही स्वीकृति मिल सके। इसके तहत एनवाईसीएस ने ओला चालकों और टैक्सी, ऑटो-रिक्शा तथा वाणिज्यिक वाहनों के अन्य स्थानीय चालकों सहित 6,000 चालकों का प्रशिक्षण और मूल्यांकन पूरा कर लिया है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के पांच शहरों लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर और नोएडा में क्रियान्वित की जा रही है जिसमें 1500 से अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

आयोजक:

नेशनल युवा को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

गेल इंडियन स्पीडस्टार: एनवाईसीएस गेल इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी में 11 से 17 वर्ष की आयु के बालक-बालिकाओं के लिए एक अनूठा अखिल भारतीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम 'गेल रफ्तार इंडियन स्पीडस्टार' का सफलतापूर्वक आयोजन कर रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा प्रतिभाओं की खोज, चयन, पोषण और संवर्धन करना तथा उन्हें एथलेटिक्स में ओलंपिक पदक जीतने के लिए प्रशिक्षित करना है। इस प्रतिभा खोज कार्यक्रम में 4,50,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कौशल्या सेतु अभियान: एसएससी परीक्षा पास करने में कठिनाई का सामना करने वाले छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चलाई जा रही 'कौशल्या सेतु अभियान' परियोजना में एनवाईसीएस कार्यान्वयन भागीदार है। इस परियोजना का उद्देश्य महाराष्ट्र के हाई स्कूल ड्रॉपआउट छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह परियोजना महाराष्ट्र के 34 जिलों के 111 प्रशिक्षण केंद्रों में क्रियान्वित की गई है।

पर्यटन व सहकारी संस्थाएं : चुनौतियां व अवसर राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी

इंडिया का खेलोत्सवः इस कार्यक्रम के माध्यम से हजारों एथलीटों ने प्रतिस्पर्धा की। इंडिया का खेलोत्सव स्पोर्ट्स एक्सपो में खेल प्रशासकों को सम्मानित किया गया। एनवाईसीएस एथलीटों को चैंपियन बनाने के लिए मजबूत समर्थन देती है। खेलोत्सव में एनवाईसीएस के एथलीट निसार अहमद ने अंडर-17 की 100 मीटर स्पर्धा में 10.96 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक जीता। पी डेनिनल ने 800 मीटर में स्वर्ण और ताई बाम्हने ने 1500 मीटर में कांस्य पदक जीता।

जन औषधि केंद्रः किफायती दवाओं के स्टोर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने में एनवाईसीएस रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की एजेंसी बीपीपीआई (भारतीय फार्मा पीएसयू ब्यूरो) का एक कार्यान्वयन भागीदार है। एनवाईसीएस 7 राज्यों में 22 केंद्र खोलने में सफल रही है।

जैव ऊर्जा उत्सवः पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एनवाईसीएस और महरत्ता चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के सहयोग से जुलाई 2017 में शिव छत्रपति क्रीड़ानगरी, बालेवाड़ी और पुणे में एक विशाल कार्यक्रम 'जैव ऊर्जा उत्सव' का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जैव ऊर्जा क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डालना था ताकि एक समावेशी राष्ट्रीय नीतिगत ढांचा विकसित किया जा सके। एनवाईसीएस ने 10 अगस्त, 2017 को देश भर के 100 स्थानों पर जैव ऊर्जा कार्यक्रम आयोजित करके विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया।

रिसर्जेंट इंडिया युवा कॉन्क्लेवः युवाओं का सशक्तीकरण करने वाले इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य आने वाले दशक में युवाओं के लिए एक रोडमैप तैयार करना है। इस कॉन्क्लेव में सरकार, उद्योग, शिक्षा, नीति-निमार्ता और नागरिक समाज के विभिन्न हितधारकों को युवाओं के आर्थिक समावेशन और सशक्तीकरण के लिए नीतियां बनाने के उद्देश्य से एक मंच पर लाया गया।

युवा मंथन: 2018 में आयोजित यह दो दिवसीय कार्यक्रम नीति निमार्ताओं और कार्यान्वयनकताओं के लिए विकासात्मक योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के मार्गदर्शक सिद्धांतों को समझने हेतु एक साझा मंच था।

युवा एक्सपो: युवा एक्सपो एनवाईसीएस का एक इवेंट मैनेजमेंट डिवीजन है। इसने 2006 में नई दिल्ली, 2008 में रायपुर, 2011 में नई दिल्ली और 2013 में भोपाल में युवा को-ऑप एक्सपो का आयोजन किया था। इस एक्सपो में प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया और युवा सशक्तीकरण पर अपने बहुमूल्य अनुभव साझा किए, जिससे प्रतिनिधियों को भारत में उद्यमिता और देश के आर्थिक विकास में युवाओं की भूमिका के बारे में प्रोत्साहन मिला।

ग्रामीण होमस्टे परियोजना: बैक टू विलेज (बी2वी) के सहयोग से एनवाईसीएस मध्य प्रदेश के बैतूल और छिंदवाड़ा के 4 आदिवासी गांवों में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ग्रामीण होमस्टे परियोजना पर काम कर रही है। इस परियोजना के तहत प्रत्येक गांव में कम से कम 10 होमस्टे बनाए जा रहे हैं। ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत के रूप में इसके तहत विभिन्न सामूहिक गतिविधियों (ग्रामीण खेल, लोक नृत्य, लोक संगीत, नाटक, भजन आदि) पर भी काम किया जा रहा है।

पहली बार कच्छ में बनी नमक कोऑपरेटिव

युवा सहकार टीम

गुजरात के कच्छ के नमक उत्पादकों को संगठित करने, उन्हें बाजार से जोड़ने, उनके लिए इनपुट सेवाएं उपलब्ध कराने और उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने के लिए पहली बार नमक क्षेत्र में सहकारी समिति का गठन किया गया है। इस समिति के माध्यम से नमक उत्पादन से होने वाला मुनाफा सीधे उन श्रमिकों और उत्पादकों तक पहुंचेगा जो कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं। कच्छ के नमक उत्पादकों को सहकारी ढांचे के माध्यम से सशक्त बनाने की दिशा में यह क्रांतिकारी कदम है। यहां देश के कुल नमक उत्पादन का करीब 87 प्रतिशत उत्पादन होता है।

जीसीएमएमएफ और सरहद डेयरी ने संयुक्त रूप से किया श्री कच्छ जिला दरिया कंथा विस्तरणी मीठा उत्पादक और वहेचन सहकारी मंडली लिमिटेड का गठन

नमक उत्पादकों के सशक्तीकरण के इस ऐतिहासिक कदम की शुरूआत गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (जीसीएमएमएफ) और सरहद डेयरी ने की है। दोनों के संयुक्त प्रयास से श्री कच्छ जिला दरिया कंथा विस्तरणी मीठा उत्पादक और वहेचन सहकारी मंडली लिमिटेड का गठन हुआ है। जीसीएमएमएफ ही अमूल ब्रांड नाम से दूध और विभिन्न दुग्ध उत्पादों का कारोबार करती है जो एक इंटरनेशनल ब्रांड है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के चार वर्ष पूरे होने के अवसर पर गुजरात के आणंद में आयोजित एक कार्यक्रम में देश की पहली नमक सहकारी समिति का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री अमित शाह ने कहा, 'यह समिति सहकारिता आंदोलन के एक नए युग की शुरूआत है। कच्छ जिला नमक सहकारी समिति एक मॉडल सहकारी समिति के रूप में कार्य करेगी, जो पारंपरिक नमक उत्पादकों (अगरियाओं) को संगठित

कर उन्हें अमूल जैसे प्रभावशाली सहकारी ढांचे से जोड़ने का काम करेगी। नमक उत्पादन देश का एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो अब तक सहकारी ढांचे से जुड़ा नहीं था, लेकिन अब यह कमी पूरी हो गई है।' उन्होंने इस पहल के पीछे प्रमुख प्रेरणाशक्ति रहे हुंबल भाई का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि उनका प्रयास इस समिति की आधारशिला बना।

कच्छ के रण में सदियों से नमक उत्पादन से जुड़ा अगरिया समुदाय अत्यंत कठिन परिस्थितियों में कार्य करता है। समाज के वंचित वर्गों से आने वाले इस समुदाय को अब तक बिचौलियों और असंगठित व्यवस्था के कारण अपने श्रम का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता था। अगरिया समुदाय के सदस्यों को एक साझा सहकारी मंच पर लाकर यह समिति उन्हें उचित मूल्य, लाभ में हिस्सेदारी और संस्थागत समर्थन प्रदान करेगी जिससे उनकी पारंपरिक आजीविका को नई ताकत मिलेगी। सहकारिता मॉडल के अंतर्गत उन्हें सामाजिक सुरक्षा और एक सम्मानजनक जीवन की दिशा में भी समर्थन मिलेगा। कच्छ नमक सहकारी समिति के गठन से यह सुनिश्चित होगा कि नमक उत्पादन से जुड़े सभी मजदूरों को संरचित और सामुदायिक नेतृत्व वाली व्यवस्था के माध्यम से न केवल स्थायी आय प्राप्त हो, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव आए।

चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। देश के कुल नमक उत्पादन में कच्छ का योगदान 63 प्रतिशत है। इसकी वजह से गुजरात नंबर एक नमक उत्पादक राज्य है जो कुल 87.4 प्रतिशत का योगदान देता है। उत्पादन में दूसरे नंबर पर राजस्थान (6.7 प्रतिशत) और तीसरे पर तमिलनाडु (4.7 प्रतिशत) का स्थान है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा, हिमाचल प्रदेश और दमन व दीव का स्थान है जो देश के नमक उत्पादन में कुल 1.2 प्रतिशत का योगदान देते हैं। नमक उत्पादन के मुख्य स्रोतों में समुद्री जल के अलावा, झीलों का लवणीय जल, भूमिगत लवणीय जल और सेंधा नमक के भंडार हैं। अरब सागर के तटीय इलाके पर स्थित कच्छ का नमक उत्पादन में विशेष महत्व है। यहां का अगरिया समुदाय पारंपरिक रूप से इसके उत्पादन से जुड़ा है। नमक की खपत खाने और औद्योगिक क्षेत्र दोनों में होती है। भारत में लगभग 74 लाख टन नमक की घरेलू खपत और 125 लाख टन की औद्योगिक खपत होती है। भारत में संगठित नमक उत्पादन की संभावनाएं बहुत अधिक है। देश में इसके उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। आजादी के समय 1947 में भारत नमक का आयात करता था और तब मात्र 19 लाख टन उत्पादन हुआ था। अब भारत इसका निर्यात करता है। 2022-23 में रिकॉर्ड 39.11 लाख

- **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के चार वर्ष पूरे होने के अवसर पर किया समिति का शुभारंभ**
- **कच्छ के 77 हजार से ज्यादा उत्पादकों को इस समिति से मिलेगा लाभ, शुरूआत में 3,000 अगरिया नमक कोऑपरेटिव से जुड़े**
- **अभी 19,000 करोड़ रुपये का है भारत का नमक उद्योग जिसके 2034 तक बढ़कर 34,000 करोड़ रुपये हो जाने का है अनुमान**

शुरुआत में इस समिति से 3,000 से ज्यादा अगरिया जुड़े हैं। उनके द्वारा उत्पादित नमक की यह समिति सीधी खरीद करेगी, उन्हें प्रोसेस किया जाएगा और जीसीएमएमएफ के मजबूत नेटवर्क के तहत बेचा जाएगा। जीसीएमएमएफ द्वारा डेयरी क्षेत्र में अमूल की सफलता की कहानी को नमक क्षेत्र में भी दोहराए जाने की उम्मीद है।

टन नमक का उत्पादन देश में हुआ था। वर्ष 2024 में भारतीय नमक बाजार 9,000 करोड़ रुपये का था, जिसके वर्ष 2034 तक लगभग दोगुना होकर 35,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

शुरुआत में इस समिति से 3,000 से ज्यादा अगरिया जुड़े हैं। उनके द्वारा उत्पादित नमक की यह समिति सीधी खरीद करेगी, उन्हें प्रोसेस किया जाएगा और जीसीएमएमएफ के मजबूत नेटवर्क के तहत बेचा जाएगा। जीसीएमएमएफ द्वारा डेयरी क्षेत्र में अमूल की सफलता की कहानी को नमक क्षेत्र में भी दोहराए जाने की उम्मीद है। इस मॉडल को बाद में राजस्थान, तमिलनाडु और अन्य नमक उत्पादक राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। अमूल डेयरी मॉडल से प्रेरणा लेते हुए यह सहकारी संस्था जीसीएमएमएफ के व्यापक वितरण नेटवर्क के माध्यम से उत्पादकों को प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग से सीधे जोड़ेगी। इससे अगरिया लोगों को सदस्यों के रूप में संगठित किया जाएगा, जिससे उन्हें शोषणकारी आपूर्ति श्रृंखलाओं और कर्ज के जाल से निकलने में मदद मिलेगी। यहां के नमक उत्पादकों का दशकों से शोषण किया जा रहा है। ये लोग उत्पादन के लिए 8-9 महीने तक मेहनत करते हैं। उन्हें उपभोक्ता द्वारा नमक के एक पैकेट के लिए भुगतान की जाने वाली राशि का केवल 2 प्रतिशत हिस्सा मिलता है। जबकि एक ब्रांडेड नमक उपभोक्ता नमक के एक पैकेट के लिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम तक का भुगतान करता है। इसके मुकाबले अगरिया को केवल 50 पैसे प्रति किलोग्राम मिलते हैं।

नमक आयुक्त की एक रिपोर्ट के अनुसार, कच्छ के 77,000 से अधिक अगरिया आजीविका के लिए नमक उद्योग पर निर्भर हैं। इनमें से ज्यादातर दूरदराज के इलाकों के हैं जहां काम करने की परिस्थितियां कठोर हैं। लगभग 88 प्रतिशत छोटे नमक किसान हैं जिनके पास 10 एकड़ से कम जमीन है। इसकी वजह से अक्सर उनके पास सौदेबाजी की शक्ति या आधुनिक प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे का अभाव होता है। भारत का नमक उद्योग मजबूत है लेकिन उत्पादक स्तर पर कम संगठित है। विशाल तटीय संसाधनों और बढ़ती वैश्विक मांग के साथ सहकारी ढांचा इस क्षेत्र को मजबूत और इसके उत्पादकों को समृद्ध बनाएगा। ■

सहकारी समितियों को मिलेगी आर्थिक मजबूती

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनसीडीसी की 2,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय अनुदान सहायता योजना को दी मंजूरी

अनुदान सहायता के आधार पर एनसीडीसी चार वर्ष की अवधि में खुले बाजार से 20,000 करोड़ रुपये जुटा सकेगी

इस धनराशि से सहकारी संस्थाओं को नए प्रोजेक्ट शुरू करने, संयंत्रों के विस्तार तथा ऋण प्राप्त करने में मिलेगी सहायता

युवा सहकार टीम

सहकारी समितियों की नई परियोजनाओं को स्थापित करने, उनके संयंत्रों का विस्तार करने और उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को 2,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का प्रावधान वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट में किया था। अब सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। एनसीडीसी की केंद्रीय अनुदान सहायता योजना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति दी गई। वित्त वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक की इस योजना के तहत प्रत्येक वित्त वर्ष में एनसीडीसी को 500 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता दी जाएगी। इस अनुदान सहायता के आधार पर एनसीडीसी चार वर्ष की अवधि में खुले बाजार से 20,000 करोड़ रुपये जुटा सकेगी, जिसका उपयोग सहकारी समितियों की वित्तीय सहायता के रूप में की जाएगी।

इसके माध्यम से देश भर में डेयरी, पशुधन, मत्स्य पालन, चीनी, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और कोल्ड स्टोरेज जैसे विभिन्न क्षेत्रों की 13,288 सहकारी समितियांऔर श्रमिकों एवं महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों के लगभग 2.90 करोड़ सदस्य लाभान्वित होंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक योगदान देने वाली इन समितियों के लिए दीर्घकालिक और कार्यशील पूंजी ऋण सहयोग आवश्यक है। सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक उत्थान के अलावा आधारभूत ढांचे विकसित करने और रोजगार उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देश में उत्पादन के सभी क्षेत्रों में सहकारी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। देश में 8.25 लाख से अधिक

रोजगार सृजन क्षमता

एनसीडीसी द्वारा सहकारी समितियों को दी गई धनराशि से आय उत्पन्न करने वाली पूंजीगत परिसंपत्तियां सृजित होंगी और सहकारी समितियों को आवश्यक कार्यशील पूंजी तरलता प्राप्त होगी। इससे उन्हें अपनी क्षमता बढ़ाने, आधुनिकीकरण करने, विविध गतिविधियां संचालित करने, उत्पादकता और लाभ बढ़ाने तथा अधिक रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी। इससे सदस्य किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सावधि ऋण, विभिन्न कौशल कार्यबलों में रोजगार के व्यापक अवसर भी उत्पन्न होंगे। आर्थिक लाभों के अलावालोकतंत्र, समानता और सामुदायिक सरोकारों के अपने सिद्धांतों के माध्यम से सहकारी समितियां सामाजिक-आर्थिक अंतर को पाटने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के आवश्यक साधन हैं।

सहकारी समितियां हैं जिनमें 29करोड़ से अधिक सदस्य हैं। देश के 94 प्रतिशत किसान किसी न किसी रूप में सहकारी समितियों से जुड़े हुए हैं।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कैबिनेट द्वारा एनसीडीसी की अनुदान सहायता को मंजूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि'के मंत्र पर चलते हुए एनसीडीसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 2,000 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता से सहकारी संस्थाओं को नए प्रोजेक्ट शुरू करने, संयंत्रों के विस्तार तथा ऋण देने में सहायता मिलेगी। इससे सहकारिता से जुड़े करोड़ों सदस्य लाभान्वित होंगे, महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस कल्याणकारी निर्णय के लिए देश भर के सहकारी क्षेत्र की ओर से मोदी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।'

अमित शाह ने कहा, 'किसानों का कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसी दिशा में एक और महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने 'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना' के लिए कुल 6,520 करोड़ रुपये के व्यय को स्वीकृति दी है, जिसमें 1,920 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी शामिल है। इस योजना के तहत 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड आयराडिएशन यूनिट्स और 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, जिससे खाद्य संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता में सुधार होगा और किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा।'

कार्यान्वयन नीति और लक्ष्य

अनुदान सहायता योजना के तहत एनसीडीसी परियोजना धनराशि का वितरण, अनुवर्ती कार्रवाई, परियोजना निगरानी और निधि से वितरित ऋण की वसूली करेगी। एनसीडीसी सहकारी समितियों को राज्य सरकार के माध्यम से या सीधे ऋण प्रदान करेगी। एनसीडीसी के प्रत्यक्ष वित्तपोषण दिशानिर्देशों के मानदंडों को पूरा करने वाली सहकारी समितियों को स्वीकार्य राशि या राज्य सरकार की गारंटी पर सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों की सहकारी समितियों को परियोजना सुविधाओं की स्थापना, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विस्तार के लिए दीर्घकालिक ऋण और उनके व्यवसायों को कुशलतापूर्वक तथा लाभप्रद रूप से चलाने के लिए कार्यशील पूंजी दी जाएगी।

महिला सशक्तीकरण

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में दी गई एक जानकारी के अनुसार, एनसीडीसी ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान महिला सहकारी समितियों को 3,504.4 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी है। महिला सशक्तीकरण की दिशा में यह बड़ी पहल है। आंकड़ों के अनुसार, एनसीडीसी ने महिला सहकारी समितियों को 2022-23 में 1,437.24 करोड़ रुपये, 2023-24 में 711.55 करोड़ रुपये और 2024-25 में 1,355.61 करोड़ रुपये वितरित किए गए। इस राशि में से करीब 2.37 करोड़ रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए दिए गए। राज्यवार आंकड़ों की बात करें, तो एनसीडीसी की आर्थिक सहायता में सबसे आगे आंध्र प्रदेश रहा, जिसे कुल 3,185.24 करोड़ रुपये मिले। इसके बाद तेलंगाना को 295.11 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र को 20.25 करोड़ रुपये मिले। इसके अलावा तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों को भी आर्थिक सहायता मिली है। इस पहल का मकसद महिला सहकारी समितियों को मजबूत बनाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। ■

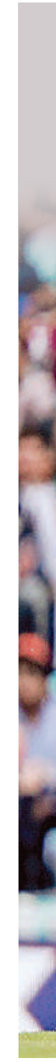

टेस्ट में बेस्ट गिल की युवा टीम

सत्येन्द्र पाल सिंह

पच्चीस बरस के शुभमन गिल ने बतौर कप्तान अपनी पहली ही टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ बल्ले से अनुकरणीय प्रदर्शन किया। गिल ने बल्ले के धमाल से पांच टेस्ट मैचों की क्रिकेट सीरीज दो-दो से ड्रॉ करा अपने आलोचकों को गलत साबित कर दिया। इस यादगार प्रदर्शन की नायक पूरी टीम है। गिल की युवा टीम ने दिखा दिया कि वह टेस्ट में बेस्ट है। भारतीय क्रिकेट के मुख्य राष्ट्रीय चयनकर्ता अजित आगरकर और टीम इंडिया के चीफ कोच गौतम गंभीर ने शुभमन गिल को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की कप्तानी सौंपते हुए साफ कर दिया था कि नतीजा चाहे जो रहे, उन्हें यह जिम्मेदारी लंबे समय के लिए दी गई है।

गिल की अगुआई में यह कामयाबी टीम इंडिया की पुरानी सुपर स्टार संस्कृति पर भी कड़ा प्रहार है। अतीत में कई धुरंधरों को करियर के अंत में संघर्ष करने के बावजूद बराबर मौका दिया गया। विराट कोहली और रोहित शर्मा जब इस साल के शुरू में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने गए थे तब इन दोनों को मालूम था कि उनके करियर की सांझ दस्तक देने लगी है। गिल की अगुआई वाली भारतीय टीम को अब अगले साल श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ उसके घर में टेस्ट सीरीज खेलनी है। भारत की नौजवान टीम पूरे जोश और जुनून से इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट की सीरीज खेली और हर टेस्ट पांच दिन तक चला। इससे यह साफ हो गया कि टीम इंडिया आज भी टेस्ट क्रिकेट खेलने को बेताब है और इसे

इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज 2-2 से रही ड्रॉ, युवाओं से लैस टीम इंडिया ने दिखाया जोश और जुनून

चीफ कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल के फैसलों ने आलोचकों को गलत साबित किया

> टीम चयन को लेकर लोगों की अपनी राय हो सकती है। जब आपका फैसला सही होता है तो लोग उसकी सराहना करेंगे। जब आपका फैसला सही नहीं रहता है तो लोग आपको निशाने पर लेंगे। मुझे इसे लेकर कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मानना है कि मैं हमेशा टीम हित में सर्वश्रेष्ठ फैसला लेता हूं।
>
> **शुभमन गिल**
> कप्तान

सबसे ज्यादा तवज्जो देती है। टीम इंडिया की जीवटता, जज्बे और इंग्लैंड को उसके घर में कड़ी टक्कर से यह भी साफ हो गया कि टेस्ट क्रिकेट अभी जिंदा रहेगी। टेस्ट क्रिकेट को बोझिल बता कर इसे चार दिन का करने की वकालत करने वाले आलोचकों के मुंह पर भी इससे ताला लग गया। पांचों टेस्ट के पूरे 25 दिन इंग्लैंड के स्टेडियम क्रिकेट प्रेमियों से खचाखच भरे रहे।

भारत ने इंग्लैंड की बहुचर्चित बेजबॉल क्रिकेट की बहुत हद तक हवा निकाल दी। युवा तुर्कों से सजी टीम इंडिया द्वारा ओवल के आखिरी टेस्ट मैच में मात्र छह रन से चमत्कारिक जीत हासिल कर सीरीज को बराबरी पर समाप्त कराना जीत से भी बड़ा था। भारत इस साल के शुरू में विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन की मौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया में पांच टेस्ट की सीरीज 1-3 से हार गया था। ओवल टेस्ट के आखिरी दिन मोहम्मद सिराज ने बाजी पलटते हुए नाटकीय ढंग से जीत दिला सीरीज को ड्रॉ करवा दिया और टीम को शर्मसार होने से बचा लिया। गिल के नौजवान साथियों ने सदाबहार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और केएल राहुल के साथ सीरीज ड्रॉ कराने में अहम भूमिका अदा की। इस सीरीज में भारत लंबे समय बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन के बिना खेलने उतरा था। क्रिकेट पंडितों ने सीरीज से पहले कहा था कि इन धुरंधरों के बिना कप्तान शुभमन गिल और चीफ कोच गौतम गंभीर के मार्गदर्शन वाली यह टीम मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ टिक ही नहीं पाएगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। भारत को विराट, रोहित और अश्विन की सीरीज में याद ही नहीं आई।

कार्यभार प्रबंधन के चलते टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पूर्व तय कार्यक्रम के मुताबिक तीन ही टेस्ट खेल पाए। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि कप्तान गिल ने पांच टेस्ट की दस पारियों में एक दोहरे शतक सहित कुल चार शतक जड़ सबसे ज्यादा 754 रन बनाए और मैन ऑफ द सीरीज रहे। एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने में वह अब बस ऑस्ट्रेलिया के महान डॉन ब्रैडमैन के 810 रन (1936-37) से ही पीछे हैं। गिल में उनके आदर्श विराट कोहली और रोहित शर्मा, दोनों की बल्लेबाजी और कप्तानी की मिली जुली झलक देखने को मिली। कप्तान के रूप में वह इसलिए सफल रहे क्योंकि उन्होंने खुद बल्ले से दमदार प्रदर्शन किया।

अंतिम एकादश में खालिस गेंदबाजों को न चुन कर ऑलराउंडरों को चुनने के उनके फैसले पर सवाल उठाए गए थे। इसके जवाब में गिल ने कहा था, 'टीम चयन को लेकर लोगों की अपनी राय हो सकती है। जब आपका फैसला सही होता है तो लोग उसकी सराहना करेंगे। जब आपका फैसला सही नहीं रहता है तो लोग आपको निशाने पर लेंगे। मुझे इसे लेकर कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मानना है कि मैं हमेशा टीम हित में सर्वश्रेष्ठ फैसला लेता हूं। कोच गौतम गंभीर ने दौरा शुरू होने से पहले कहा था कि दुनिया भले हमारी टीम को नौजवान टीम कहे, लेकिन हमारी टीम में दुनिया की किसी भी टीम को ध्वस्त करने का दम है।'

भारत के अनुभवी सलामी बल्लेबाज केएल राहुल सीरीज में दो शतकों और दो अर्द्धशतकों की बदौलत कुल 532 रन बना सीरीज बराबरी पर समाप्त कराने के सूत्रधार बने। दाएं पैर की उंगली में चोट के बावजूद मैनचेस्टर के चौथे टेस्ट की पहली पारी में अर्द्धशतक जड़ने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज उपकप्तान ऋषभ पंत ने लीडस के पहले टेस्ट की दोनों पारियों में शतक जड़ने के साथ तीन अर्द्धशतक लगाए और कुल 479 रन बनाए। ऋषभ विश्व क्रिकेट में अकेले बल्लेबाज हैं जिससे दुनिया की हर टीम खौफ खाती है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स तक मानते हैं कि ऋषभ पंत पर बतौर बल्लेबाज लगाम लगाना बेहद मुश्किल है।

इंग्लैंड दौरे में उन्होंने टेस्ट की जरूरत के मुताबिक आक्रमण के साथ अपना मजबूत डिफेंस भी दिखाया। वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने पांच टेस्ट की नौ पारियों में जब सबसे ज्यादा 23 विकेट चटकाए, तो सवाल उठे कि उन्हें मैन ऑफ द सीरीज क्यों नहीं चुना गया। भारत की ओर से सीरीज में कुल जड़े 12 शतकों में से चार अकेले कप्तान शुभमन गिल ने, टीम के दीवार केएल राहुल, बिंदास यशस्वी जायसवाल, उपकप्तान ऋषभ पंत ने दो-दो तथा रवींद्र जडेजा और वशिंगटन सुंदर ने एक-एक शतक जड़ा। भारतीय टीम ने सीरीज में कुल 3,809 रन बनाए और पहली बार आठ बार एक पारी में 350 रन का आंकड़ा पार किया।

इंग्लैंड ने बेजबॉल यानी पहली ही गेंद से टेस्ट में दे दनादन की अपनी नीति से भले ही लीडस का पहला टेस्ट पांच विकेट से और लॉडर्स टेस्ट गिरते पड़ते 22 रन से जीता। जबकि भारत ने कप्तान शुभमन गिल के पहली

टीम इंडिया की जीवटता, जज्बे और इंग्लैंड को उसके घर में कड़ी टक्कर से यह साफ हो गया कि टेस्ट क्रिकेट अभी जिंदा रहेगी। टेस्ट क्रिकेट को बोझिल बता कर इसे चार दिन का करने की वकालत करने वाले आलोचको के मुंह पर इससे ताला लग गया।

पारी में दोहरे शतक और दूसरी पारी में शतक की बदौलत बर्मिंघम में दूसरा टेस्ट 336 रन और ओवल का आखिरी टेस्ट नाटकीय ढंग से छह रन से जीता। मैनचेस्टर का टेस्ट दूसरी पारी में कप्तान गिल, रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर के शतकों से गजब का जीवट दिखा ड्रॉ कराया। भारत ने जिन दो टेस्ट में बुमराह (तीन टेस्ट में 14 विकेट) को आराम दिया उसमें सिराज ने प्रसिद्ध कृष्णा (तीन टेस्ट में 14 विकेट) और आकाश दीप (तीन टेस्ट में 14 विकेट) के साथ मिलकर अनुकरणीय गेंदबाजी की और भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा की। भारत ने लीडस के पहले टेस्ट के आखिरी चरण में गेंद से और लॉडर्स के तीसरे टेस्ट में कुछ ज्यादा सूझबूझ दिखाई होती तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। बुमराह की गैरमौजूदगी में भी दो टेस्ट जीतने का उल्लेख करने का मकसद उन्हें कतई कमतर नहीं आंकना है। बावजूद इसके, यह भी सच है कि बुमराह अपने शागिर्द सिराज के दमदार प्रदर्शन पर खुद भी गर्व महसूस कर रहे होंगे।

ऑलराउंडर शार्दूल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर को तवज्जो दे अंतिम एकादश में खिलाने और बाएं हाथ के लेग स्पिनर कुलदीप यादव और आखिरी टेस्ट में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को एक-एक मैच के साथ अभिमन्यु ईश्वरन को एक भी टेस्ट नहीं खिलाने के फैसले की पूर्व टेस्ट कप्तान रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर और टेस्ट ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू तक ने आलोचना की। यह मानना चाहिए कि इंग्लैंड की पिचों के मिजाज को गंभीर और गिल ने सही पढ़ा। वाशिंगटन सुंदर ने एक शतक और एक अर्द्धशतक के साथ चार टेस्ट में 284 रन बनाए और 7 विकेट चटकाए। वहीं रवींद्र जडेजा ने पांच टेस्ट में एक शतक व पांच अर्द्धशतक सहित कुल 516 रन बना तीसरे स्थान पर रहने के साथ सात विकेट लेकर गंभीर और गिल के भरोसे को सही साबित किया। भारत की नौजवान टीम ने सीरीज को ड्रॉ करवा कर खुद को दमदार टीम साबित किया जो किसी भी टीम को ध्वस्त कर सकती है। यह वाकई भारतीय टेस्ट के भविष्य के लिए शुभ संदेश है। ■

(लेखक वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं।)

सफलता में एनवाईसीएस बनी मददगार

एनवाईसीएस से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आशी ने सिलाई-कढ़ाई के क्षेत्र को बखूबी समझा। लगातार प्रैक्टिस से उसके हुनर को सराहना मिलने लगी। आशी ने अपने घर पर ही टेलरिंग का काम शुरू किया। आज वह स्वरोजगार के माध्यम से अच्छी कमाई कर रही हैं और अपने स्वरोजगार को आगे बढ़ाने में जुटी हैं।

युवा सहकार टीम

जिंदगी में सफल होने के लिए मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन जिन्हें सही मार्गदर्शन मिलता है सफलता उन्हीं के कदम चूमती है। नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस) कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को सफल बनाने के लिए सही राह दिखाती है। दिल्ली निवासी 20 वर्षीय आशी वर्मा भी ऐसी ही युवती हैं जिन्होंने एनवाईसीएस से टेलरिंग में कौशल विकास की ट्रेनिंग ली और आज स्वरोजगार के माध्यम से अच्छी कमाई कर रही हैं।

युवा सहकार से बातचीत में आशी वर्मा ने कहा,'मैंने अपने जीवन में देखा कि पढ़ाई तो सब करते ही हैं, लेकिन केवल पढ़ाई से जीवन के संघर्ष मेंपास नहीं हो सकते। मैंने अपनी इस सोच को दोस्तों के साथ साझा किया, तो उन्होंने मुझे एनवाईसीएस के कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र के बारे में बताया। फिर मैंने वहां जाकर केंद्र के परियोजना समन्वयक से पता किया। उन्होंने कौशल विकास का महत्व बताते हुए बताया कि आज के समय में युवा पीढ़ी को सफल व्यवसाय शुरू करने के लिए कौशल प्रशिक्षण आवश्यक है। उन्होंने मुझे बताया कि एनवाईसीएस इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम के सहयोग से निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देती है। इसके तहत सेल्फ एम्प्लॉयड टेलरिंग, सीसीटीवी इन्स्टॉलेशन और टेक्नीशियन के तीन महीने के कोर्स करवाए जाते हैं। मैंने टेलरिंग कोर्स में दाखिला ले लिया।'

तीन महीने के प्रशिक्षण के दौरान आशी ने सिलाई, कढ़ाई से संबंधित काफी कुछ सीखा। आशी एनवाईसीएस की ट्रेनर श्रीमती शशिकला का विशेष धन्यवाद देती हैं जिन्होंने सारे विद्यार्थियों को अच्छी ट्रेनिंग दी। लिखित और व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद केंद्र ने कौशल मूल्यांकन के माध्यम से एक परीक्षा आयोजित की। इसके कुछ समय बाद प्रमाण-पत्र वितरण समारोह आयोजन किया गया जिसमें सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) द्वारा प्रमाणित सभी प्रशिक्षुओं को को प्रमाण-पत्र व अंकपत्र दिया गया।

आशी बताती हैं, 'एनवाईसीएस से प्रशिक्षण लेने के बाद मुझे नौकरी का प्रस्ताव मिला, मगर स्नातक की परीक्षा होने के कारण मैंने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मुझे पहले से सिलाई से संबंधित कुछ चीजें पता थी। प्रशिक्षण केंद्र आने के बाद मुझे प्रोफिशिएंसी मिली और बुनियादी वित्तीय ज्ञान भी मिला। इसके फलस्वरुप मैंने अपनी पढ़ाई के साथ-साथ अपने और अपने घर वालों के लिए अच्छे डिजाइन के कपड़े खुद सिलने लगी।'

एनवाईसीएस से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आशी ने सिलाई-कढ़ाई के क्षेत्र को बखूबी समझा। लगातार प्रैक्टिस से उसके हुनर को सराहना मिलने लगी। आशी ने अपने घर पर ही टेलरिंग का काम शुरू किया। आज वह स्वरोजगार के माध्यम से अच्छी कमाई कर रही हैं और अपने स्वरोजगार को आगे बढ़ाने में जुटी हैं। इसके लिए वह एनवाईसीएस को धन्यवाद देना नहीं भूलती हैं। ■

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
NANO TECHNOLOGY
NANO UREA & DAP
IFFCO KISAN DRONE
असरदार जोड़ी
नैनो यूरिया प्लस
सागरिका
नैनो डी ए पी
IFFCO
NANO UREA PLUS
IFFCO
Wholly owned by Cooperatives
सागरिका
SAGARIKA
100% प्राकृतिक समुद्री उत्पाद
IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
NANO DAP
(8:16:0)
CROP NUTRITION REDEFINED
Less Cost, More Profits
इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड
इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक सेंटर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017, भारत
फोन नंबर- 91-11-26510001, 91-11-42592626, वेबसाइट www.iffco.coop
इफको नैनो उर्वरकों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया स्कैन करें"

NYCS

National Yuva Co-operative Society Limited

Empowering Financial Independence

Our Services

Loans: Small, medium, and large loans at highly competitive interest rates, catering to the diverse financial needs of our members.

Deposits: Attractive interest rates, with special benefits for senior citizens and women.

Simplified Process: Our streamlined application process and flexible terms ensure that financial assistance is always within reach.

Our Reach

- Presence in All States & Union Territories
- 37 Branches Nationwide
- 600+ Districts Served by Our Representatives
- Central Administration Office (CAO) in Pune, Led by Senior Banking & Finance Professionals

Why Choose NYCS Ltd.?

- **Trusted Expertise** – Over 20 years in financial services.
- **Nationwide Presence** – A rapidly growing network.
- **Member-Focused** – Tailored financial solutions.
- **Youth Empowerment** – Supporting young entrepreneurs.

Contact Us

209, 2nd Floor, A2B,
Vardhman Janak Market,
Janakpuri, New Delhi-58
+91 9205595944
011-45096652/40153681
nycs.ltd@gmail.com
www.nycsltd.com

Together, letls build a brighter financial future!